जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 232 प्रभात बीकानेर, बुधवार 18 मार्च, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

क्या कांग्रेस विघटन की ओर अग्रसर है?

तीन राज्यों में कांग्रेस विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया

- **चर्चाओं के अनुसार, राज्यसभा चुनावों में भाजपा का प्रलोभन कम नहीं थाः 5 करोड़ रूपए व एक फॉर्च्यूनर।**
- **सहयोगी दलों में भी यह भावना फैल रही है, और दुख की बात है कि कांग्रेस में अब जवाबदेही व जिम्मेवारी निभाने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है।**
- **राज्यों के नये-नये प्रभारी वो लोग हैं, जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर पाते, अतः ये प्रभारी अपना मैसेज स्पष्ट रूप से व सख्ती से आगे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचा नहीं पाते हैं और इससे पार्टी में अनुशासन लागू नहीं हो पाता।**

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मार्च। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी नेतृत्व खुद को बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि तीन राज्यों में हुए राज्यसभा चुनावों में विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया। आरोप है कि भाजपा ने भारी धनराशि के प्रस्ताव देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया।

चुनाव प्रबंधन और पार्टी संचालन के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम की कार्यशैली पर।

हरियाणा में पांच कांग्रेस विधायकों ने आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, जबकि चार विधायकों के वोट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खारिज कर दिए गए। कांग्रेस उम्मीदवार केवल 0.03 प्रतिशत अंतर से जीत सका, वह भी इसलिए कि एक भाजपा विधायक का वोट अमान्य हो गया था।

इसके अलावा, इंडियन नैशनल लोक दल (आईएनएलडी) के दो विधायकों को मतदान नहीं करने दिया गया। यह भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रणनीतिक चूक मानी जा रही है, जिन्हें लगा था कि उनके वोट नहीं पड़ेंगे तो भाजपा दूसरे वरीयता वोटों से जीत जाएगी।

कांग्रेस उम्मीदवार की जीत किस्मत से हुई और कहा जा रहा है कि वे बाल-बाल बच गए। वे राहुल गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में नेता और कार्यकर्ता, दोनों ही उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे।

ओडिशा में बीजू जनता दल-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के तीन विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे ने चुनाव जीत लिया। वे तीसरी बार राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं।

ओडिशा में सोफिया फिरदौस, जो पार्टी नेतृत्व की करीबी मानी जाती हैं, ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया। अन्य दो विधायक, जो जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। इससे राहुल गांधी द्वारा जिला अध्यक्षों को सशक्त बनाने की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बिहार में भी कांग्रेस-राजद गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के तीन विधायकों और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान किया।

इस घटनाक्रम के बाद, राजद में कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। सहयोगी दलों में यह धारणा बनती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है और उसमें जवाबदेही की कमी है।

वरिष्ठ नेताओं पर भी कार्रवाई न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कई प्रभारियों की नियुक्ति की है, जो न तो जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद कर पा रहे हैं और न ही पार्टी में अनुशासन कायम कर पा रहे हैं।

एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, यह कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर बुरी खबर है, पार्टी बिखरती नज़र आ रही है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायकों को लुभाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये और एक फॉर्च्यूनर जैसी पेशकश की गई।

बच्चा गोद लेने वाली महिला को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा

नई दिल्ली, 17 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में बच्चा गोद लेने वाली सभी माताओं के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के रास्ते खोल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ को तीन माह से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने तक

- **सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा कोड में संशोधन किया।**

सीमित करने वाले कानून को भेदभाव वाला बताते हुए पुनर्परिभाषित कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने सामाजिक सुरक्षा कोड की धारा 60(4) को बच्चा गोद लेने वाली माताओं के साथ भेदभाव करने वाला करार दिया है। यह धारा बच्चा गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश को सीमित करती थी। इसमें कहा गया है कि बच्चा गोद लेने वाली माताएं मातृत्व लाभ पाने की तभी पात्र होंगी, जब गोद लिया गया बच्चा तीन महीने से कम उम्र का हो।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी भी उम्र का यानी तीन महीने से ज्यादा आयु का बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब अमेरिका इज़रायल ग्रुप का ईरान से वार्ता करना और कठिन हुआ

ईरान के पुराने प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ व कुटनीतिज्ञ लारिजानी भी मारे गए, मंगलवार को इज़रायल की बमबारी में

- **अब, जब यूरोपीय देशों ने व नाटो के सदस्यों ने अमेरिका-इज़रायल के ईरान के साथ हो रहे युद्ध में भागीदार बनने से साफ मना कर दिया तो अमेरिका-इज़रायल को ईरान के उस नेता को ढूंढना जरूरी हो गया था, जिससे वे किसी भी तरह से युद्ध समाप्ति व शांति स्थापित करने की बात कर सकें।**
- **अली लारिजानी, ग्यारह साल ईरान की संसद के स्पीकर रहे हैं तथा उनका परिवार ईरान के राजनीतिक हल्कों में काफी असरदार माना जाता है। अली के पांच भाई हैं और ईरान की राजनीति में निर्णायक पदों पर रहे हैं। एक भाई तो ईरान की न्यायपालिका के कई साल मुखिया रहे हैं।**
- **अब विश्व के अन्य देशों को भी ऐसा नेता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, जो व्यवहारिक हो तथा अपने राजनीतिक रुतबे के कारण युद्ध की समाप्ति की बात कर सके।**

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मार्च। मंगलवार को इज़रायली हमले में ईरान के एक और प्रमुख नेता की हत्या कर दी गई, जिससे देश नेतृत्व विहीन होकर और भी गहरे राजनीतिक संकट में फंस गया है। अली लारिजानी, जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख थे, और कथित तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद व्यावहारिक रूप से देश का नेतृत्व कर रहे थे, इस हमले में मारे गए।

अली खामेनेई की हत्या और लगभग 40 अन्य शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद, ईरान में सत्ता का बड़ा खालीपन पैदा हो गया था, जिसे आंशिक रूप से लारिजानी भर रहे थे।

खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए उनके दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई के भी एक अन्य हमले में गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। शीर्ष पद पर चुने जाने और उनके घायल होने की खबरों के बाद से मोजतबा को न तो व्यक्तिगत रूप से देखा गया और न ही उनकी आवाज़ सुनी गई है। इसके बदले, उनके संदेश पढ़कर सुनाए जा रहे हैं।

लारिजानी, जो ईरान की राजनीतिक संरचना के शीर्ष स्तरों की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंगाल के बाद असम और तमिलनाडु में भी अफसर बदले चुनाव आयोग ने

इन राज्यों के कई जिलों में पुलिस प्रमुखों को हटाने का आदेश दिया

- **असम में चुनाव आयोग ने पांच जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाने के साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव ड्यूटी से दूर रखने का निर्देश दिया। यही नहीं, असम के मुख्य सचिव से बुधवार तक अनुपालना रिपोर्ट देने को कहा है।**
- **आयोग ने तमिलनाडु में भी चार जिलों के पुलिस प्रमुखों को हटाया है तथा उन्हें चुनाव ड्यूटी में वंचित कर दिया है।**
- **चुनाव आयोग ने 2010 से 2021 के बैच के योग्य अफसरों की लिस्ट भी मांगी है, ताकि, उन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा सके।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मार्च। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में प्रशासनिक बदलाव तेज कर दिए हैं। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि असम और तमिलनाडु में भी कई जिला पुलिस प्रमुखों को हटाया गया है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

असम में चुनाव आयोग ने पाँच जिला पुलिस प्रमुखों को हटा दिया है। माजुली, साउथ सलमारा, सदिया, चिरांग और धेमाजी के एसएसपी का तबादला किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी ड्यूटी में तैनात न किया जाए। आयोग ने असम के मुख्य सचिव से बुधवार तक अनुपालन रिपोर्ट देने को भी कहा है।

इन तबादलों के साथ ही, चुनाव आयोग ने 2010 से 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं, ताकि उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर्स-डीईओ) के रूप में तैनात करने पर विचार किया जा सके। मुख्य सचिव से कहा गया है कि वे योग्य अधिकारियों की सूची समीक्षा के लिए आयोग को भेजें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द

नई दिल्ली, 17 मार्च। लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष के आठ सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसका ध्वनिमत से सभी ने समर्थन किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ सोमवार को सभी दलों के नेताओं संग हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर पक्ष-

- **केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने इसका प्रस्ताव रखा जिसका सभी ने ध्वनिमत से समर्थन किया।**

विपक्ष में चल रही तनातनी का हल निकालने के लिए इन सदस्यों का निलंबन खत्म करने पर यह सहमति बनी थी। इन सदस्यों में सर्वश्री गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन थे।

वरुण गांधी लौट के मोदी की शरण में आए

वरुण गांधी ने एक्स पर मोदी के साथ अपने परिवार की फोटो पोस्ट की

- **पोस्ट में वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा, प्रधानमंत्री से उन्हें पिता जैसा स्नेह व संरक्षण का भाव मिला। मुझे यकीन है, वे देश की जनता के सच्चे संरक्षक हैं।**
- **समझा जाता है कि वरुण को प.बंगाल चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी यामिनी रॉय चौधरी बंगाली हैं और वरुण गांधी वहाँ दामाद वाली भावनाएं जगाकर पार्टी को लाभ दिला सकते हैं।**
- **ज्ञातव्य है कि वरुण गांधी 2021 के किसान आंदोलन के समय से ही पार्टी नेतृत्व के विरोधी रहे हैं, मुफ्त राशन, वंदे मातरम्, जैसे मुद्दों पर उन्होंने पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना की थी और एक समय यह चर्चा भी थी कि वे कांग्रेस में चले जाएंगे।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मार्च। पूर्व पीलीभीत सांसद वरुण गांधी, भाजपा नेतृत्व के साथ लंबे समय तक तनावपूर्ण संबंधों के बाद, आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नज़र आ सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2021 के किसान आंदोलन से शुरू होकर, वरुण का पार्टी नेतृत्व से टकराव होता रहा है। विशेष रूप से लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत पर किए गए उनके आलोचनात्मक ट्वीट्स के बाद यह टकराव और खुलकर सामने आ गया था। इससे पहले, उन्होंने बेरोज़गारी, सरकारी पदों का खाली रहना और केन्द्र सरकार की कई नीतियों पर सरकार और भाजपा की आलोचना की थी, जिसमें प्रमुख उज्ज्वला योजना में मौजूद कमियों की बात भी शामिल थी। उन्होंने सरकार की मुफ्त राशन योजना की भी आलोचना करते हुए कहा था कि मुफ्त राशन बेरोज़गारी का विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि "जय श्री राम" और "भारत माता की जय" जैसे नारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते।

इस बीच ऐसी चर्चाएँ भी थीं कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उसी दौरान बद्रीनाथ में उन्हें राहुल गांधी के साथ भी देखा गया था।

मंगलवार को वरुण ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा की, जिसमें उनकी पत्नी यामिनी रॉय चौधरी और बेटी अनसूया भी साथ थीं। यह तस्वीर, और उसके साथ की गई वरुण की टिप्पणी, उनके राजनीतिक "वनवास" के अंत का संकेत देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा करते हुए लिखा, "मुझे अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने पितृसुलभ स्नेह और सुरक्षा की भावना का अनुभव कराया। इस मुलाकात के बाद मुझे और अधिक विश्वास हो गया है कि आप भारत के लोगों के सच्चे संरक्षक हैं।"

भाजपा नेतृत्व द्वारा वरुण को बंगाल अभियान में शामिल करने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, उनकी पत्नी यामिनी के बंगाली हैं, इसलिए वे "दामाद" वाली भावना को भुना सकते हैं। दूसरा, वरुण का बंगाल के युवाओं से पुराना जुड़ाव और अनुभव है, क्योंकि 2013 में वे भाजपा के महासचिव के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

वरुण के प्रदर्शन के आधार पर यह भी संभव हो सकता है कि आने वाले महीनों में खाली होने वाली उत्तर प्रदेश की किसी सीट से उन्हें राज्यसभा में समायोजित कर दिया जाए।

टीएमसी ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किये

कोलकाता, 17 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें युवा तथा अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई

- **मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वापस भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी।**

है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि दार्जिलिंग क्षेत्र की तीन सीटों पर तृणमूल चुनाव नहीं लड़ेगी।

पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कालीघाट स्थित अपने आवास से 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, उन्हें पार्टी संगठन में अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ी थीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब गुजरात में लागू होगी यूसीसी

नई दिल्ली, 17 मार्च। गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने की तैयारी तेज हो गई है। उच्च स्तरीय समिति ने आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दिया। यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। इसमें राज्य के सभी धर्मों व

- **सेवा निवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई ने यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पटेल को सौंपी।**

समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों पर एकसमान कानूनी ढ ांचे की सिफारिशें शामिल हैं।

समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। समिति ने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारी अंतर्कलह से हरियाणा की राज्यसभा सीट हारते-हारते बची कांग्रेस

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की "मिस कैलकुलेशन" ने कांग्रेस को सीट दिला दी

- **नायब सिंह सैनी ने इंडियन नैशनल लोकदल के दो विधायकों को वोटिंग से दूर रखा, उन्हें लगा, उनके वोट नहीं पड़ेंगे तो भाजपा का दूसरा प्रत्याशी भी दूसरी वरीयता के वोटों से जीत जाएगा। पर इससे जीत के लिए आवश्यक वोट कम हो गए और कांग्रेस को फायदा मिला।**
- **हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं, इनमें 48 भाजपा के 37 कांग्रेस व दो आइएनएलडी एवं तीन निर्दलीय हैं। आइएनएलडी के वोटिंग से दूर रहने के कारण 88 विधायकों ने ही वोट डाला, पांच वोट अवैध घोषित हुए तो वैध मत 83 ही रह गए, इससे जीत के लिए आवश्यक आंकड़ा 28 वोट का रह गया।**
- **भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को 39 वोट मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर को जीत के लिए आवश्यक 28 वोट मिले व तीसरे प्रत्याशी सतीश नांदल को 16 वोट मिले। अगर भाटिया के 11 सरप्लस वोट दूसरी वरीयता के रूप में नांदल को मिल जाते तो उनके 27 वोट हो जाते, ऐसे में कांग्रेस से एक और क्रॉस वोटिंग होती या भाजपा के एक अवैध मत वैध हो जाता तो से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ सकता था।**
- **कांग्रेस के कुल 37 विधायक हैं, 5 ने क्रॉस वोटिंग की और चार वोट अमान्य हो गए, यानि, 9 वोट पार्टी के हाथ से निकल गए। इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा के परस्पर विरोध को कारण माना जा रहा है।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 मार्च। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर की गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी की संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया और पार्टी राज्यसभा सीट हारते हारते बची, निर्दलीय प्रत्यशी को अनुमान से ज्यादा वोट मिल गए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का तनाव चुनाव के दौरान फिर सामने आ गया, जिससे राज्य इकाई में एकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसका असर मतदान के पैटर्न में दिखा, जहां कांग्रेस के कम से कम 5 विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग की, जबकि चार अन्य के वोट अमान्य घोषित हो गए।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह नेतृत्व की विफलता का मामला है। उनका मानना है कि विपक्ष के नेता और अनुभवी नेता हुड्डा को पार्टी के भीतर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए था। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप ने स्थिति और बिगाड़ दी है, और बताया जा रहा है कि हुड्डा खेमे ने शैलजा गुट पर क्रॉस-वोटिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

इस विवाद के बीच, कांग्रेस नेतृत्व अब उन विधायकों की सूची तैयार कर रहा है, जिन पर क्रॉस-वोटिंग का संदेह है, ताकि पार्टी के राज्यसभा प्रयास को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा सके।

इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। पार्टी नेताओं, अभय सिंह चौटाला और आदित्य देवी लाल ने कहा कि यह फैसला जनभावना को ध्यान में रखकर लिया गया, हालांकि उनकी अनुपस्थिति ने भी अंतिम परिणाम को प्रभावित किया।

90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में आईएनएलडी के दो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

CMYK